कोटि की कम लागत वाली फिल्मों के निर्माण हेतु तथा सिनेमा उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए फिल्म वित्त निगम स्थापित किया हुआ है । कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने अपने राज्यो में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अपने अपने फिल्म विकास निगम स्थापित किए हुए हैं ।

लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए खनिजों का सर्वेक्षण

3929. **श्री श्याम लाल धुर्वे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खनिजो तथा वन उत्पादो जैसे कच्चेमाल से सपन्न जिलो का सर्वेक्षण कराने की कोई योजना है ताकि उनसे सबंधित लघु और कुटीर उद्योगो की स्थापना करने के लिए उपयुक्त स्थानो का पता लगाया जा सके ,

(ख) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नही, तो इस उद्देश्य के लिए अब तक योजना न बनाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयती) : (क) स्थानीय स्रोतो, स्थानीय कुशलता और स्थानीय माग के आधार पर लघु तथा कुटीर उद्योगो की स्थापना करने की दृष्टि से लगभग सभी जिलो का सर्वेक्षण किया जा चुका है । जिला उद्योग केन्द्रो के कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिस मे देश के सभी जिले थोडी सी अवधि मे ही आ जाऐगे, विद्यमान लघु तथा कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन देने और नये औद्योगिक क्रिया कलाप की स्थापना के लिए सर्वेक्षणो की समीक्षा की जायेगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नही उठते ।

राजभाषा अधिनियम, 1968 के उपबन्धों की क्रियान्विति

3930. **श्री राम प्रसाद देशमुख :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या उन के मत्रालय/विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1968 और उस के अन्तर्गत जून, 1976 मे बनाये गये नियमो के बारे मे अपने सबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयो को सूचना दे दी है तथा क्या उन्हें इनको क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है ,

(ख) यदि हा, तो मत्रालय/विभाग ने उत्तर दिया है कि उक्त उपबधो और नियमो का पूरी तरह मे पालन किया जा रहा है, और

(ग) यदि नही, तो उस के क्या कारण है और उक्त नियमो का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण अडवाणी) : (क) जी हा ।

(ख) और (ग). यथा सशोधित राजभाषा अधिनियम तथा राज भाषा (सघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के उपबन्धो को यथा सम्भव हद तक कार्यान्वित किया जा रहा है । उक्त अधिनियम और नियमो के उपबन्धों का पूरी तरह पालन न होने के मुख्य कारण है पर्याप्त अनुवाद सुविधाओ और हिन्दी टाइपिस्टो आदि की कमी तथा अधिकाश अधिकारियो/ कर्मचारियो का हिन्दी मे प्रवीण न होना या हिन्दी मे काम करने का अभ्यस्त न होना । उक्त अधिनियम और नियमो के उपबन्धो का पालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है :–

(1) मंत्रालय के विभिन्न सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयो से प्राप्त हिन्दी के

प्रयोग सम्बन्धी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की जांच की जाती है और उन में पाई जाने वाली कमियों को सम्बन्धित कार्यालयों के ध्यान में लाया जाता है और उन से उन्हें दूर करने के लिए कहा जाता है ।

(2) मंत्रालय की राज भाषा कार्यान्वय समिति अपनी आवधिक बैठकों में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करती है और हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी विभिन्न आदेशों के कार्यान्वयन पर बल देती है ।

(3) हाल ही में मंत्रालय के कुछ कार्यालयों में हिन्दी अनुवादकों, हिन्दी टाइपिस्टों आदि के कुछ पदों का सृजन किया गया है और कुछ अन्य कार्यालयों में इस प्रकार के पदों के सृजन के प्रस्तावों के बारे में कार्रवाई चल रही है।

(4) कर्मचारियों को हिन्दी/हिन्दी टाइपराइटिंग/हिन्दी आशुलिपि में सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

Black Marketing by Digvijay Cement

3931. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Digvijay Cement and its subsidiaries are black marketing the imported Korean Cement in Bombay and the local cement production reduced considerably; and

(b) if so, steps taken to stop black marketing?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) and (b). No specific instance of black marketing of imported cement has come to the notice of the Government.

The Sewree grinding unit of M/s. Digvijay Cement Co. has a licensed capacity of 16.667 tonnes per month. Against this, the production so far during 1978 has been:

January	.	21,289 tonnes
February	.	16,027 tonnes
March	.	11,816 tonnes (upto 14-3-1978)

M/s. Digvijay Cement Company have been appointed as one of the handling agents for handling and distribution of imported cement at Bombay. Their rate of unloading the ships has been around 2,000 tonnes per day against the stipulated minimum discharge of 1,000 tonnes per day. The quantity discharged has been despatched by M/s. Digvijay Cement Company to release order holders as well as cement-stockists as per directions of the Regional Cement Controller. No quantity of cement has been kept by them in their godown as unsold.

Establishing a Permanent Coast Guard Organisation

3932. SHRI AGHAN SINGH THAKUR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish a permanent coast guard organisation to guard the countries coast line;

(b) if so, the time by which the organisation is expected to be established; and

(c) the strength and the responsibilities of the organisation?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Coast Guard Organisation is expected to come into being during the current year. Details in this regard are yet to be finalised.